

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 18 अंक 189

सक्षम प्रशासन

हाल के हफ्तों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धांचे में काफी सुधार दिखे। इस सुधार से पहले तो कर दरे सरल बनाकर जीएसटी व्यवस्था को एक नया रूप दिया गया। अब जीएसटी व्यवस्था में मुख्य रूप से केवल दो दरे रह गईं और कुछ अधिकतर वस्तुओं पर ऊंचे कर को प्राधान्य कम किया गया। इस कदम से जीएसटी की संरचना काफी सरल हो गई है।

पूँचाव को वित्त मंत्री मॉर्गेन सातोसमान ने जीएसटी और बड़ा पंचतार (जीएसटीएलटी) की शुरूआत की जिसे एक ही अक्षरों पर सुधार माना जा रहा है। जीएसटी की संरचना में इस कदम की कमी मरसूस हो रही थी। कानून में इस कड़ा का जिक्र है मगर कुछ चुनौतियों के कारण इसकी स्थापना में विलंब हो गया। इसका नतीजा अब बड़ा होगा कि जीएसटीएलटी 4,80,000 अरबों के लिए अति-बड़े को केथ अथवा नया काम शुरू करेगा।

इस तरह का मुख्य पीछा राष्ट्रीय राजधानी में होगा और अलग वित्त वर्ष से यह अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय असील प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इस तरह यह कर प्रशासन में स्पष्टता लाने में मदद करेगा। इस पंचाट में 31 राज्य पीछा होंगे और प्रत्येक में दो न्यायिक सदस्य और केंद्र और राज्य दोनों से एक तकनीकी सदस्य होंगे। थारू में राज्य पीछों, जिनमें एक न्यायिक सदस्य में प्रवास था, को चुनौती दी गई थी। कानून के अंगरेजी जैसीस्टों की त्रि-स्तरीय असील संपर्कना का प्रवाधान है निम्नलिखित फले असील प्राधिकरण, उसके बाद असील न्यायिक प्रणाली या पीछा और अंत में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय हैं। अब असील पंचाट को शुरुआत के साथ जैसीस्ट प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और तेजी आनी चाहिए।

अब इस पंचाट की स्थाना हो चुकी है और यह अखिल पर सुभाषी गुरु कर रहा है, इसलिए कुछ पहलुओं पर मैं नैन नजर रखना चाहती होंगी। हमसे पहले पीठों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ एवं मानक संसाधन होना चाहिए। बड़ी तादाद में मामले धूल फेंक रहे हैं जिन पर जल्ले से जल्द मुकदमा दर्ज होना। पंचाट में क्षमतावान् चुनौतियों से इसका हाथ भी बृद्ध न्यायिक प्रणाली की तरह हो सकता है। इस बिंदु पर विचार करना ज़रूरी है कि स्थानों के पास पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएँ नही होने से दूरस्थ सोलर एवं उद्देश्य वाले कानून की अस्थिर नतीजें हो दे पाते हैं। ऋण सोयन अक्षमता एवं दिव्याला संसिता का हाल हम देखे हो चुके हैं। असाधारण दूर, जिनके लिए ऑनशु रूप से क्षमतावान् बाजारों की जिम्मेदारी, से नजीजी पर गंभीर असर हो रहा है। हमें यह बात अवश्य समझनी होगी कि व्यावसायिक मामलों में सम्पधान में देरी होने से कांदाव कर पर लागत खासी बढ़ जाती है। पर्याप्त क्षमता के अभाव से उत्पन्न चुनौतियों के कारण निर्णयों की गुणवत्ता पर भी असर होता है जिससे न्यायपालिका में कंठ स्तरों पर बोज़ काफी बढ़ जाता है।

कर अधिकारियों को कारोबारों के खिलाफ कदम उठाने से पहले अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। कर की अत्यधिक मांग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों के मामलों में कारोबारियों का बच जगह है जिन्हें दूर करना जरूरी है। यह कोई नहीं कर रहा है कर चोरों को बचाने के बजाय के खिलाफ कारोबारों नहीं होनी चाहिए। इन बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सही एवं ईमानदार कारोबारियों को बेवजह प्रताड़ित नहीं होना पड़े। इसके अलावा, जीएसटी प्रणाली को कर श्रेणियों में होने से यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सरल हो जाएगी मगर प्रशिक्षणों की और सरल बनाने की जरूरत है। प्रशिक्षण के अलावा विवाद रख्ये हो कम हो जायेंगे। जी भी हो, देखें के बावजूद अपील चणों की स्थापना के आधार पर जीएसटी तंत्रों की कार्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। विचारार्थी लोगों का समाधान होने से संबंधित पक्षों के लिए स्पष्टिा स्पष्ट हो जाएगी और संभवतः भविष्य में कानूनी विवाद भी कम हो जायेंगे। इन बातों के बावजूद जीएसटीएटी के अंतर्गत निष्ठा (फैडरल) में होने वाली प्रगति पर करीबन रस रखनी होगी।

सरकार की नीति में बदलाव और असर

मांग को बढ़ावा देने के लिए कर लाभों का सहारा लेना यह दिखाता है कि सरकार नया रास्ता अपना रही है लेकिन यह कई नई चुनौतियों से रूबरू करा सकता है। बता रहे हैं एके भट्टाचार्य

रखिवार को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से आवाज प्रमुख निष्कर्ष यह निकल कर आया कि सरकार ने आर्थिक वृद्धि दिए पर लाने और उसे निरंतर गति देने के लिए अपनी नीति में थोड़ी तब्दीली की है। बेरोजगार, उनके संबोधन का मुख्य उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परियोजना जोषित करने में संशोधन और 450 से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर और भी कटौती के अनिवार्य के संभावित प्रभाव से राष्ट्र को निगमन कहना था। तथाकथित 'बचत का उत्सव,' जो प्रधानमंत्री को नजर में लाया था, कटौती दर में कटौती से शुरू होने वाला था, घोषित लक्ष्य था। लेकिन उस लक्ष्य के पीछे उनकी सरकार को आर्थिक नीति में बदलाव प्रस्पष्ट दिखाई दे रहा था।

कोविड महामारी के बाद के वर्षों में मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि पट्टी पर लाने के लिए दोआयमी दृष्टिकोण अपनाया। एक तरफ केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे में लगातार कमी लानी शुरू कर दी जो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9.2 फीसदी से अधिक था और 2024-25 में कम होकर 4.77 फीसदी तक सिमट गया। दूसरी तरफ, सरकार ने बेहतर वृद्धि मिश्रण के माध्यम से राजकोषीय मजबूती हासिल करने की कोशिश की। इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि होने के बावजूद राज्यस व्यय में कमी आई।

केंद्र सरकार का राजस्व व्यय वर्ष

2020-21 में जीडीपी के 15.5 फीसदी से घटकर 2024-25 में 10.9 फीसदी तक गया जहाँक उन्त अवधि में ही उसका पूंजीगत व्यय जीडीपी के 2.15 फीसदी से बढ़कर 7.1 फीसदी हो गया। वैश्वक राजस्व के तैजी से काफी मदद मिली और इससे पिछले कुछ दशकों में केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में सर्वाधिक तेजी से कम आई। यय 2020-21 में जीडीपी के 7.3 फीसदी से कम होकर 2024-25 में 1.71 फीसदी रह गया। इस तरह, कोविड महामारी के बाद के वर्षों में सरकार की नीति राजकोष व्यय घटा नियाँत रखने, अपना राजस्व व्यय कम करने और निजी क्षेत्र की हिव्यकिचाहट के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक खर्च करने पर केंद्रित था।

अगर प्रभलमन्त्री के राष्ट्र के नाम संयोजन को कोई संकेत माना जाए तो ऐसा लगता है कि वह नीति मान बजल रही है। 'बचत का उत्सव' आर्थिक वृद्धि को दोबारा धाक देने और इसे निरंतर बकएर प्रवृत्ति के लिए एए नया नीतिगत जोरिया प्रतीत हो रहा है। प्रभलमन्त्री ने जीएसटी दर के युक्तिकरण को उपभोक्ताओं के हाथों में आधे खर्च यौय रकम डालने के माध्यम के रूप में देखा। उम्मीत तो अरब खर्ची जा रही है कि उपभोक्ता कर कटौती से बची रकम बचती की ड़ीली में डालने के बजाय खर्च करेगी। अगर उपभोक्ता को खरीदना का इस्तेमाल करतु एवं सेवाओं की खरीदारी के लिए खर्च करतु है तो इससे मांग में नई जान फूँकेन,

क्षमता इस्तेमाल बढ़ाने और निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि जीएसटी दर में कटौती और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में दी गई आश्वासन राहत यानी 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कर दर शून्य करने से लोगों की कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये सालाना बचत होनी चाहिए। वह रकम जीडीपी के लगभग 0.75 फीसदी के बराबर है, जो दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में मांग प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी।

पञ्चमर्गियों के संघर्षांचे में रागात्मिकता सँभरी भी साफ दिखती है। देखा जाय़ा-उन्हीं उम्मीद जताई कि उद्योग उपभोक्ताओं के लिए कीमती धरा कर दर में कटौती का लाभ देने में संकोची नहीं होगी। एके केवल एक आश्रमा मजा जा सकता था, क्योंकि जीएसटी व्यवस्था में अब मुनाफ़ाधारों पर लगी निम्न नई हैं जिन्हें उन उद्योगों पर लागू किया जा सके जो दर में कटौती का लाभ नहीं देते हैं। फिलहाल तो यही लग रहा है कि उद्योग जीएसटी दर के वृद्धिकरण का उपयोग अपनी विक्री बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देश को बड़ी बड़ों वाहन निर्माण कंपनो ने अपने वाहनों की बीमातों में विशेष तत्पर पर इन्की सीटों की कमियाँ में यह जल्दी कटौती से मिलने वाले लाभ से कहीं अधिक है। इससे पता चलता है कि कंपनी विक्री और बाजार हिस्सेदारों बढ़ाने के लिए दर में कटौती का

पूरा लाभ उठाना चाहती है।

सूत्र, लघु और मध्यम उद्यमों में भी ज़ोरसदीरें देर कम होने के बाद धेरुलु विनिमरण वढ़ाने की अपील की गई है। स्देशरी या आर्थिक आसरमर्भरने के विचार का प्रथमर्भरने न एक वार फिर सरभन किया है। यरहं तक कि उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि वे विदेश से आयातित वस्तुओं की जगह देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को अधिक वरीयता दें। ज़ोरसदीरें देरों में एक महत्त्वपूर्ण कतीती की प्रष्टुर्भरने में स्देशरी के एक नए रूप का संयोजन एक नया हर्दुकिण है। जिसकी वकालत प्रथमर्भरने ने अपने संयोजन के माध्यम से की है। यरहं तक कि रज्यों को भी वस्तुओं के धेरुलु विनिमरण को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।

कर सुधार को स्वदेशी और देश के आर्थिक कायाकल्प को जोड़ने से जरूरी आर्थिक लाभ मिलेंगे या नहीं यह तो समय ही बताएगा। क्या इस प्रकार के स्वदेशी अभियान का मतलब यह है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण दिया जाएगा? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी के आह्वान के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और कारोबार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों में सुधार के लिए एक बड़ा अतिरिक्त प्रयास किया जाएगा या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।

लेकिन आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मांग प्रोत्साहन तैयार करने की दिशा में बदलाव निश्चित रूप से कई सालों बाद ही संभव हो पाएगा। लेकिन मांग प्रोत्साहन को सरकार अपने वादा महिनों में राजकोषीय संकटों को कैसे अपने बढ़ावा चाहती है। ध्यान दें कि मोदी सरकार ने कोविड महामारी के तत्काल बाद मांग प्रोत्साहन से जान-बूझकर परहेज किया था और उसके बजाय बुनियादी ढांचे के निर्माण और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए उसने अपने स्तर पर निवेश बढ़ाकर अर्गुमैंत शुरू दुरुस्त करने पर ध्यान दिया था। यह कई अर्थशास्त्रियों ने तब कर कटौती के माध्यम से मांग प्रोत्साहन नहीं बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना की थी। लेकिन अब कोविड महामारी के चार साल बाद सरकार

कर रियायतों के माध्यम से मांग बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए उस दुष्टिकोण को अनामत हो दिख रहा है।

यह हो सकता है कि यह नीतिगत बदलाव नीति निष्कारकों के इस अनुभव का नतीजा हो कि सरकार के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि के चार साल बाद केवल कुछ निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से अपेक्षा परिणाम नहीं मिला है। वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि घटकर 6.5 फीसदी रह गई और शायद घटकर 6 के गिने देने पर और इसे बनाए रखने की तत्काल जरूरत ने सरकार को उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का बोझ कम करने के लिए प्रेरित किया होगा।

ये रियायतें कर को तर्कसंगत बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन नवीन वर्षों में इस तरह के बदलाव से कुछ अल्पकालिक जोखिम और चुनौतियाँ सामने आएंगी। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में संकेत दिया जा चुका है कि पिछले चार वर्षों में अपनाए गए उपायों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4 फीसदी तक समेटने का लक्ष्य है लेकिन कोविड महामारी के बाद पहली बार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय वज्र में थोड़ी गिरावट आने वाली है।

जैसे ही दूर के युक्तिकरण से राज्य में कर्मियों को आने की आशा का है जिससे निर्यात उद्योगों और रक्षा प्रतिष्ठानों को भी सहयोग देने के उपायों पर अधिक व्यय करने की मांग बढ़ सकती है। इन सबके बीच प्रस्तावित राजकोषीय प्रजन्तरी का लक्ष्य प्राप्त करने की राह में नई चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं, खासकर उन्हें समर्थन में जब कम मुद्रास्फीति 2025-26 में निर्यात-निर्माण जल की वृद्धि दर 10.1 फीसदी से नीचे ला सकती है। लिहाज, आर्थिक वृद्धि परी पर लाने के लिए इस महत्त्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को महसूस करने और खासकर लिहाज सभी को उन संभावित चुनौतियों से निपट पाना करने का समर्थ है जिसका सामना सरकार को अपने राजकोषीय समेकन कार्यक्रम को पालन करने में करना पड़ सकता है।

मोती आंदोलन 14 पाप मूत्राणों से (ओपम) प्लेटफॉर्म का प्रयोजन करती है, जो सकाराई बॉन्ड में लेनदेन के लिए सस्ते व्यापार प्रतीक से इस्तेमाल किया जाता वाला मॉडल है। इस पर व्यापार प्रतीक जो ता सीधे व्यापार कर के सस्ते के या डिपॉजिट, ऑफ-प्लेटफॉर्म लेनदेन की रिपोर्ट करने पर होता है। मोती सकाराई बॉन्ड लेनदेन का लगभग 75 फीसदी सीधे इस मॉडल पर किया जाता है, और बाकी को अपनी रिपोर्टिंग देनी होती है। सीधे बॉन्ड में कंभ, मोती सकाराई बॉन्ड लेनदेन डेटा के प्लेटफॉर्म पर होता है और इसे सीसीआई/एडएल के माध्यम से परिष्कार किया जाता है। प्लेटफॉर्म-ओपम प्लेटफॉर्म तैयार/डेटा निवेद्यकों को भारतीय बॉन्ड बाजार तक पहुंचाने को सुविधा के लिए वैश्विक बॉन्ड प्लेटफॉर्म को भी जोड़ता है। वर्ष 2003 में स्थापित, बिलसकाराई डीजिंग सिस्टम (डीजिंग लिमिटेड, इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कोष का प्रबंधन करता है) जो सकाराई बॉन्ड, डिपॉजिट मुद्रा और ओसीसी डेपोजिटिव बॉन्डों में मुद्राओं को सुविधा देता है। यह खुदरा बाजारों जिसमें कंभ, बंधन, व्यक्तित्व और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शामिल हैं, उन्हें विश्वी मुद्रा खरीदने/बेचने के लिए प्रफरसब-प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में सहायक रही है। यह प्लेटफॉर्म सुदूर बाजारों के लिए पारदर्शिता और बेहतर मूल्य निर्यापन करता है।

अब सवाल यह है कि इन व्यंनों में सीसीआईएल कैसे बढ़ रही है? वित्त वर्ष 2002-03 में, हमने 0.4 लाख करोड़ डॉलर मुद्रा के विदेशी मुद्रा लेनदेन देखा था। वित्त वर्ष 2025 तक, विदेशी मुद्रा लेनदेन की मात्रा बढ़कर 12 लाख करोड़ डॉलर हो गई है। इस अवधि के दौरान, रीपो लेनदेन 9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 779 लाख करोड़ रुपये हो गया और साधारण सरकारों बॉन्ड लेनदेन, 11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपये हो गया। अपनी नीति सहायक कंपनियों के साथ, सीसीआईएल के बढ़ते वित्तीय वाजवीकरणों के लिए एक मजबूत परिस्थितिको तंत्र बनाया है जो एकीकृत समायोजन है और जो व्यापार जीवनचक्र के हर चरण का अभ्यन्तक बना है। इस तरह से ही हमें मुद्रा बाजार प्रणाली में सीसीआईएल की भूमिका बढ़ा कर अहम है।

▶ आपका पक्ष

संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के भाषण की गंभीरता

इस समाचार पत्र में प्रकाशित सम्यक्कीय 'संयुक्त राष्ट्र में ट्रेप' राष्ट्रपति का 'संयुक्त राष्ट्र डॉनल्ड ट्रंप के भाषण के विभिन्न पहलुओं व सामग्री रखता है। भारत स्थित विश्व के सभी बड़े देशों में अवैध राष्ट्रपति का समस्या गंभीर है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी आज्ञाकारी नीति कायम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका सहित यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देश काफी समय से अवैध पुनर्पैठियों की समस्या से काफी परेशान हैं। उनके भाषण का दूसरा पक्ष संयुक्त राष्ट्र की विफलता को लेकर है जिसका मूल कारण फंडिंग नहीं है। विश्व भर में नाटो, यूरोपियन संघ, क्लाड, ब्रिक्स, आसियान जैसे समानांतर क्षेत्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र की परिस्थिति बना कर



अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था

है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के नियमों की बाध्यता है परंतु इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र का भी यूएफ मोडल है जिसको उन्होंने देशों ने नकार रखा है। फिर संयुक्त राष्ट्र

की विफलता की शिकायत किससे है? अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप वास्तविक विषयों पर अतिरेक प्रतिक्रिया करके आलोचना का केंद्र बन जाते हैं।

विनोद जाँहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in

पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर

पाकिस्तान और सऊदी अरब
के बीच समझौता

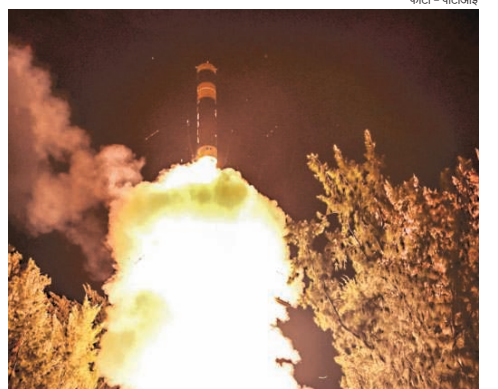
पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब के साथ रणनीतिक पावरफुल रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर यह संदेश देना कि कोशिश की है कि वह मुस्लिम जगाम में अपनी भूमिका और महत्व को पुनः स्थापित करना चाहता है। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इसकी प्रकृति को देखते हुए इसे नाटो जैसे सामूहिक गठबंधन की श्रेणी में रखा जा सकता है। सऊदी अरब की निता खाकी देशों की सुझाव और इनजुबिल है, जवफन सभापित खरते से जुडी है, उरफक पाकिस्तान का इट्टिकोण परंपरागत रूप से भारत केन्द्रित रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने नए

समीकरण गढ़ने की कोशिश में है और यह समझौता उसी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। दूसरी ओर, भारत ने हाल के वर्षों में सऊदी अरब के साथ रिश्तों को गहरा देने में पर्याप्त निवेश किया है। ऐसे में यह समझौता भारत की कूटनीतिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है। सऊदी-पाकिस्तान संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। पाकिस्तान निर्माण से पहले ही प्रिंस फैसल ने संयुक्त राष्ट्र में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान योजना का समर्थन किया था। सऊदी अरब पाकिस्तान को मान्यता देने वाला

शुरूआती देश रहा है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक दृष्टि से भी राहत भरा है क्योंकि वह गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और सऊदी से मिलने वाली आर्थिक मदद उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। भारत के लिए इसका सीधा संदेश यह है कि उसे अपनी विदेश नीति को और अधिक बह आयायी बनाना होगा।

सभाष बडावन वाला, रतलाम

► देश-दुनिया



फोटो - पीटीआई

डीआरडीओ ने रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने के लिए तैयार की गई है और विभिन्न उन्नत सुविधाओं से लैस है।

[illegible]

इक उठा।
भारती झांझ

ट्रंप के खोखले बयान

के रूप में विनियत किया जिससे सात अंशों या युद्धों को समान किया गया, लेकिन उनके शब्द उनके उन कार्यों को प्रभुपति में खोखले साहित्य के जो संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, हमलावरों को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। पृष्ठ नंबर १०३ की ख्याती कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड से लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान तक के संघर्षों को समान कर दिया, यहां तक कि भारत-पाकिस्तान विवाद को सुलझाना का दावा भी किया गया है और खाते हैं कि भारत ने उनके इस दावे का पुरजोर खंडन किया है। ऐसे दावे इतिहास और उनके प्रतिक्रियाओं के अनिवार्य को दर्शाते हैं। इससे भी ज्यादा खलने वाली बात उनकी ऊंचाई नाराजगी है।

ईरान पर उनके बयानों ने उनके विरोधाभासों को और उजागर कर दिया। ट्रम्प ने तेहरान के प्रति शत्रुता को बढ़ाते हुए शांति को बढ़ावा देने की बात की, वास्तविक बातचीत की बजाय टकराव की आग को हवा दी। एक संप्रभु राज्य के साथ तनाव बढ़ाते हुए, और साथ ही गाजा में इजरायल की सड़मुक्ति की रक्षा करते हुए, कोई वैश्विक शांति का अपील कैसे कर सकता है ?

एक सच्चा शांतिदूत विश्वास पैदा करता है, शक्ति संतुलन बनाता है और दुखों को रोकता है। ट्रम्प झूठे दावे करते रहते हैं, अपनी भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, और अपनी बड़त बनाए रखने के लिए चर्निदा लोगों का पक्ष लेते हैं। वह युद्ध समाप्त करने का

द्रुम के शब्दों का खोखलापन उनके विश्वदृष्टिकोण के गहरे खोखलेपन को दर्शाता है। शांति संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दोहराया जाने वाला नारा नहीं है; यह एक जिम्मेदारी है जिसका पालन निरंतरता, निष्पक्षता और मानवता के साथ किया जाना चाहिए।

योगी ने लिखी राजकोषीय बदलाव की पटकथा

उत्तर प्रदेश में देश में बहुआयामी गरीबी में सबसे तेज कमी हासिल की है, 2015-16 और 2019-21 के बीच 5.9 करोड़ से अधिक लोगों को अभाव से बाहर निकाला है। राज्य की गरीबी दर 37.68 प्रतिशत से घटकर 17.40 प्रतिशत हो गई, जो व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश का प्रत्यक्ष परिणाम है।



A cartoon illustration of a man with a shaved head and a yellow shawl, pointing towards a graph. The graph shows a green line increasing from 'Development' on the y-axis and an orange line decreasing from 'POVERTY' on the y-axis, intersecting on a grid.

विकास दर से चिह्नित थीं। सात साल बाद, संवीय लेखा परीक्षक का बहीखाता उन शुरुआती संवीयवादों का एक शान्तिशाली, अकड़ों पर आधारित खंडन प्रस्तुत करता है। ईस बदलाव का पैमाना कुकपीय है। राजकोपीय सतर्कता के विपरीत, योगी सरकारों ने एक बुनियादी सुधार के साथ एक बुनियादी पुनर्गठन किया: एक कठोर कानून-व्यवस्था तंत्र लागू करना।

अपराध और जबरन वसूली के नेटवर्क को ध्वस्त करके, इसने आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक पूर्वानुमानशीलता का निर्माण किया। इस बेहतर माहौल का उच्च-स्तरीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलनों के

माध्यम से आत्मक रूप से विपणन किया गया, जिससे नीतिगत को लाखों करोड़ रुपये की ठोस परिणोजन प्रबलबद्धता में परिवर्तित किया गया। अनुभजन सारथ समकथों: किशी भी राज्य की जनैरनेयता पर विचार करें: उसका अणन कर राज्यल/पुल्लरी सरका के अंतित वय (2016-17) में, वाणिज्य कर, उदय मुलक और खनन जैने प्रमुय मदों से राज्यल लाभ 86,000 करोड़ डॉलर था। दो वयों के भीतर, वय अंकड़ा 1.17 लाख करोड़ डॉलर से अधि हो गया - एक आबर्जनक 63 प्रतिशत की वृद्धि। खनन राज्यल, जो प्रवर्तन और औपचारिकता पर एक स्पष्ट बेरोमिड है, डेयुने से भी अधिक हो गया। यह केवल संसदी नहीं है; यह पहली की अनुपचारिक और प्रसिद्धि हुई अवलोक्यता पर

एक बलवान वक्ता को देखे रहके खेतल न बनने में बदलाव हो। ओषोमिक और राहक जिला, एक उदाहरण उसरी के मामल में स्थानीय अजसरी के चलाय में कि उज्जय की सीमाओं के के कदम गरिया बलवान हो रही है। एक ओषोमिक जो पिछली सरकारी के नहीं बदलाने न तो आकासमिक है और नही आकासमिक। यह एक ओषोमिक प्रती की क है किवा यो योमिक है - नहर स्थान, व्यापक बुनियादी ढाँच के कदम गरिया एक केन्द्रित नियमन रातिन - नहर स्थान सीमितर के साथ अनायाग योम अतीत के खराब रिर्काई से अलग

सत्वे के निर्माण, हवाई अड्डों के और स्वदेशी उद्योगों के विकास संरक्षण में न केवल तत्काल निविधि को जन्म दिया है, बल्कि मौलिक रूप से नई महत्वापी नई प्रदेश से अपनी रनिवेश-छवि को त्याग दिया है और ऐसी आर्थिक महाशक्ति के रूप में जिसकी महत्वाकांक्षी 1 दिसियन अजस्यकताप्य बनने की है।	एक कहांनी। उल्लेखनीय राजनीतिज्ञ इच्छा-आफ्राता से चुनौतियों का भी सही हबीमाकृत से प्रेक्ष अच्छी तरह से राजकोषीय अनुशासनात्मक के निशान से जोड़ है केवल अपनी केहाइ बल्कि खुद को भाषा
--	--

मी, राजस्व अधिशेष क्षमता का न कि पूर्णता का प्रमाण। यह जौंच-पड़ताल को आमंत्रित करता है। बेहतर राजकोषीय स्थिति के उत्तर प्रदेश के मानव विकास हालाँकि उल्लेखनीय रूप से बेहतर	इंजन के रूप में विरोधाभास का सम पुजारी राज्य के प्रबंधक के रूप राजकोषीय निराशा बदल दिया है।
--	---

हालाँकि, फिलहाल, राजकोपीय परिवर्तन को नकारा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के वहीखाते अतीत से अलग नहीं हैं। अक्सर योगीनाम्बाजी से भरे राजनीतिक परिदृश्य में, योगी आदित्यनाथ ने एक जबरदस्त बड़द हसिल की है: ठोस, मात्रात्मक सफलता की एक कक्षा। उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक अग्रगण्य से, शासन की सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है।

हवीमारुह से प्रकाश रतप तक का सफर अच्छी तरह से चल रहा है। यदि इस राजकीय अनुशासन को अब मानव विकास के मिशन से जोड़ा जा सके, तो उत्तर प्रदेश न केवल अपनी कहानी फिर से लिख लेगा, बल्कि खुद को भारत के भविष्य के निर्वाचक इंजन के रूप में स्थापित कर लेगा। विरोधाभास का समाधान हो गया है: तेजतर्र पुराजी राज्य के सबसे प्रभावी आर्थिक प्रबंधक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने राजकीय निराशा को शासन के चमकदार में बदल दिया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि

पूरन डावर
लेखक, चिंतक एवं
विश्लेषक हैं।

अतः त्योदय एवं एकाल्प मानववाद की अवधारणा के प्रणेता जनसंघ के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय...जब तक पॉकिंग में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सेवा नहीं पहुँचती तब तक देश विकसित नहीं कहला सकता... इस सोच के साथ जिस चिंतक ने राजनीति में शुचिता की कल्पना की... देश का दुर्भाग्य नहीं हमने समय से पहले खो दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर को

1916 ह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं कुशल राजनीतिज्ञ मिले थे। पंडित उपाध्याय ने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की कल्पना की थी, जहाँ विकास अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचे। वह वर्गहीन, जातिहीन और संघर्षमुक्त सामाजिक व्यवस्था के समर्थक थे। इस दिशा में निस्संदेह काफी प्रयास किए गए

हैं, लेकिन फिर भी काफी कुछ किया जाना शेष है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करना अति आवश्यक हो गया है। पूंजीवादी एवं समाजवादी विचारधाराएं हमें आगे होने का बोध तो करा रही हैं,

लेकिन इस बोध में एक खोखलापन है। पंडित उपाध्याय को इस खोखलेपन का भान था, इसलिए वे कहते थे कि पूंजीवादी एवं समाजवादी विचारधाराएं केवल हमारे

शरीर एवं मन की आवश्यकताओं पर विचार करती हैं, और इसलिए वे भीकानेवादी उद्देश्य पर आधारित हैं, जबकि संपूर्ण मानव विकास के लिए इनके साथ ही आत्मिक विकास भी आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय जितने अच्छे राजनेता थे, उतने ही उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। वह केवल समस्या पर ध्यान आकर्षित नहीं करते थे बल्कि उसका समाधान बताते भी थे। विश्वास रखते थे।

उन्होंने दुनिया को अंत्योदय से परिचित कराया। एक ऐसा विचार, जो सबसे पहले



और सबसे अधिक सहायता उस व्यक्ति को उपलब्ध कराने पर जोर देता है। जिसकी जरूरत सबसे अधिक है। सरल शब्दों में कहें तो जरूरतपंथी में से एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना, जिसे सहायता की आवश्यकता सबसे अधिक हो और फिर उसी से शुरूआत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक सहायता पहुँचाना। पंडित उपाध्याय मानते थे कि जिस झोंपड़ी में पहले से ही दीया जल रहा है, वहाँ बल्ब लगाने से बेहतर होगा पहले उस घर को रोशन किया जाए जो अंधकार में डूबा है। अंधेरे में जलाया गया एक छोटा सा दीपक

भी उम्मीदों के उजाले का प्रतीक बन सकता है। पंडित दीनदयाल के चिंतन को मुख्यतः अविश्व के रूप में याद किया जाता है, लेकिन एकात्म मानववाद भी उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। उनके द्वारा स्थापित एकतात्म मानववाद को परिभाषा मानव परिप्रेक्ष्य में अधिक सामथ्र्य है। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस प्रकार मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के ठीक रहने पर वह चरम सुख और वैभव को प्राप्त कर सकता है, ठीक उसी तरह यदि समाज के प्रत्येक वर्ग पर ध्यान दिया जाए तो भारत को आदर्श राष्ट्र

मानव से कोई नहीं रहने सकता। एकसिरी मानववर्ग का उद्देश्य एक ऐसा व्यवस्थापन सामाजिक-वैयक्तिक माहल विकसित करना था, जिसमें विकास के केन्द्र में मानव हो। मान्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक व्यक्ति को निर्माणपूर्ण निम्न प्रयत्न करना था। ये व्यक्ति बाद का खूबन करता है और एह पूर्ण समाज में निर्माण के लिए परिवर्तन तथा मानवत्व के महत्व को प्रोत्साहित करता है। पीपुल डिविजन उपाध्यक्ष ने कई दशक पहले ही आज को समझा और उनके समाज को रेखांकित कर दिया था। ये दृष्टांत है, उन्हें तथा था कि आधुनिक के बाद जिस तरह से पृथिवी में संकुचित, विचारधारा को अपनाने की इच्छा जगमगाते रहे रही हैं, वह और चलकर एक ही समस्या को आज देखें। विकास की दृष्टि में एक व्यक्ति समझे पीछे ठूट जाऊंगा जिस विकास के नाम पर समझ चुका जहा है। पीपुल उपाध्यक्ष के दर्शन, विचारों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है।

जैसे मौजूदा परिस्थितियों, समस्याओं को देखकर, उनका आंकलन करके ही उन्होंने उन्हें लिखा है। आज यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे बीच होते तो

11 फरवरी, 1968 को ये हम सबको छोड़ कर दुनिया में चला गए। उनका निधन आज तक पहली नावा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से पटना जा रहे थे, इसी दौरान उनका यात्रा मूल्यसारय रेलवे बार्ड में पाया गया। उनका मौत की मृत्यु खड़ापूर के लिए सीबीआई से भी जांच कराई गई, मगर कुछ क्लिफ़ नोट ही हुआ। आज मूल्यसारय रैशन कार्ड का नाम दीनदयाल नगर रवतक उनका स्मृति को संजोया गया है। रवतक मोदी सरकार दीनदयाल जी की अंत्येष्टि से प्रेरित कारक कर रही है। अंतिय व्यक्ति तम मारा सेवा नहीं, अंतिय पंक्ति में खड़ा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है—यह करके दिखा लें।

जिस तेजी से हम विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं... अंत्योदय की परिकल्पना सार्थक रूप लेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा से प्रेरित होकर ही अंत्योदय अन्तर्पूर्णा सेवा शुरू की गई।

उनके अवतरण दिवस पर उनकी स्मृति को पुनश्च नमन।

आप की बात

पहले और अब भी वोट फार मी

पहले चुनाव पूरा जर्मनीक पाँचवाँ "चेर फेर सी" के लिए होइल। लाल दल करीबी जीतल। और एकमुसल शक्ति पार्टीक पहिले से सफेक कर लेल। जर्मनीक लाल दल करीबी जीतल। और फेडरल के कुछ दिन पहिले के ओर में "लालचर मी" के नेमन मी, जिसे ओर मी माना जाइत छल, मी डाले जायेत और लालचर पार्टीक जर्मनीक ऑफिसल सामग्री मी डाले जायेत। किन्तु अब काले सामने से दौट पर मी के केमिस्टा का ठोका बल्ल मी, अब खुले आम चुनाव के ठोका बिस्तर के एगो पूरा मी घोषणा होइत छल। ई हिस्सा, जर्मनीक "बर्गेस" शब्दों के लिए पुराने मी के जहाँ स्थिति सामने होइत छल, एह सफेक दल बिचिन रहल। जर्मनीक ऑफिसल फायदे पुराने मी के जहाँ चोपित करल और पिछले बेलाकाल के ओ डाला करके लाल मी पहुँचा जाइत छल। दूसर बिचियेबे मी, एकर एगवरी सामने होइत छल। एकरा करीबी के बेलाकाल जेकरे एकर नलेब पर दलाल लालक अडिचि। खुबियावले दे के पुरा अमानावित करे किने जायेत। सेरे से लज्जा में पन होल। होल अजब होल मी होना पर "चेर फेर सी" के सफल बनने के लिए मददगारि को आइबिक करल। सेरे से लेल एकरा उन्के डाला किने होल होल। खुबिये बेलाकाल जे जर्मनीक दल के सामने में प्रहार होल को ओर ऑफिसल दल के बलाय बल के बदल होल देल, लोग को अलसर से दल रखने और जर्मन को बलाय बेकने होल अनीन बलाय सेक रखी।

लद्दाख में हिंसा

ले-लारुणमं हि स तस्य । हिंसां हिंसे पतौ तया आजन्वनी कौ यद्, किन्ती यो हृष्टे से जावन्त नही ठहराया जा सकता । हिंसा व आनन्दनी किन्ती भी समरणा न समाना नही । हिंसा से राग व रव्ये का हो दुःखन होला । पौराणिकक व सामाजिककविता समान योक्तुका । ले-लारुण को रूपा व रव्ये का द्वासे दो तल्ले विभिन मणों के लिए, आनन्द व आनन्दन कर रहे थे, उन्हे पते हिंसा व आनन्दनी का कौन्ती निन्द को बया आता । आनन्दन समाज कर रहे । विभिन मणों को लेकर हास व रव्ये से शक्ति पान आनन्दन समाज जा रहा है । लेकिन आनन्दनमणों से रव्ये समर कर कतवती नही करती, हिंसा का कतव्य बनाया जा रहा है । इन्हे समर कर को पेसे समर कर से प्राप्तिमता के लिए समर कर करवा जाता । अरु भी मणि नही हूँ है । लेले में शक्ति स्थानिरो, इन्के लिए हृष्ट समर कर को एक पजन पर लेकन बातीची पर समर कर उचित व होनाजानक हितकारी समायान समन रहने निमालना हो । समसे जावन्त चित्त होत व ले-लारुण को ले-लारुण के पडोसी शक्ति लता व भक्तिमता । ये सखनन समर कर दोषे पडोसी पता के विपदक भेदों को लतासे व रहते है । जो शक्ति में आनाना फेरते होइ किन्ती भी निमामन समर कर आता मणि में डालने का काम कर सकते है । इस समर को मणिगत से लेते हए, खरुससे ले-लारुण में शक्ति व शक्ति वरणा को दायित्व लेकर समर कर का है ।

सवाल बेटियों की सुरक्षा का

दृष्टा उसका के समान यह पक्षि भाव पूरा पूरा पक्षि के समान-साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे भारत को आधी आबादी महिलाओं एवं लड़कियों के सम गौरव के साथ-साथ सम गौरव जीवन वाला मिलाओ। उन उल्लंघन करने में सफल हो पाएँ। विचार का विषय है कि आनंद के दौर में बेटों के लिए तभी ही चुनौती-यों का अर्थ है। समाजिक तंत्र पर बेटों के प्रति हमारा समाज उदा हू आ है। लेकिन बेटों के ललामपुत्र के साथ ही बेटों को सीख देने की आवश्यकता है। अपना भाव प्रत्यक्ष दिखाने चाहिए, समाज और सरकार को निजाना होना। तभी हम इस उल्लंघन-पक्षिष्य का भार प्रशस्त कर सकते हैं। इस उल्लंघन समाज बनाता होना कि आजकल तब उनका बेना पायल या डाटा सैटों बेटों को आत्मनिर्भरता और आत्मरक्षा के पूरा सिखाएं आनंद के दौर की पहली आवश्यकता है। बेटों है तो नुकन है, इस नार को सायेंतना इस बात में निश्चित है कि बेटों को समाजिक पुरुष के लिए हमारी सरकार और समाज निजकन सवते हैं। समाजिक एवं व्यवसायिक तंत्र पर लिंग के आधार पर भेदभाव वाला मानसिकता पूरी तरह समाज के ललामपुत्र की बेटों के लिए आधी वाला कलक पूरी तरह से इस उल्लंघन फुलने का आवस्य प्रशस्त कर सके।

कब मिलेगा पीओके

[illegible]

Support me by **joining my private channel**

AND GET EARLIEST AND RELIABLE SOURCE TO READ NEWSPAPERS
DAILY.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| <u>1) Times of India</u> | <u>6) The Hindu</u> |
| <u>2) Hindustan Times</u> | <u>7) Live Mint</u> |
| <u>3) Business line</u> | <u>8) Financial Express</u> |
| <u>4) The Indian Express</u> | <u>9) Business standard</u> |
| <u>5) Economic Times</u> | <u>+All Editorial PDFs</u> |

Click below to

Join

